दृष्टि The Vision

करेंट अफेयर्स उत्तराखंड

अप्रैल (संग्रह)

2022

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

उत्तराखंड **3**

- टिहरी ज़िले के सुरकंडा मंदिर क्षेत्र में डॉपलर रडार का कार्य पूर्ण 3
- उत्तराखंड में आठ तल वाली गुफा की खोज 3
- उत्तराखंड के हर ज़िले में गठित होगी सड़क सुरक्षा समिति 3
- '1064 भ्रष्टाचार-रोधी मोबाइल ऐप' 4
- नरेंद्र सिंह नेगी 4
- प्लास्टिकमुक्त देहरादून अभियान 4
- राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड-1 में उत्तराखंड 5
- हरिद्वार में गंगा घाटों पर प्लास्टिक वस्तुओं की बिक्री पर रोक 5
- उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की कवायद 6
- बद्रीनाथ मास्टर प्लान 6
- पंतनगर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा बनाने की पैरवी 6
- व्यासी जल-विद्युत परियोजना 7
- चंद्रभागा नदी 7
- एचसी सेमवाल बने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान समिति के अध्यक्ष 7
- चंपावत में बनेगा हाई-टेक मधुमक्खीपालन प्रशिक्षण केंद्र 8
- 'प्रवेश उत्सव' 8
- वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून में मनाया गया पृथ्वी दिवस 9
- क्रांति दिवस मेला 9
- उत्तराखंड के लिये 13,707 करोड़ रुपए की मेगा निर्माण परियोजना का प्रस्ताव 9
- उत्तराखंड में बढ़ता वनाग्नि का प्रकोप 10
- सूर्यधार झील 10
- उत्तराखंड में मुख्यमंत्री से की गई शिकायतों का होगा त्वरित निपटान 10

नोट :

उत्तराखंड

टिहरी ज़िले के सुरकंडा मंदिर क्षेत्र में डॉपलर रडार का कार्य पूर्ण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राज्य मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक बिक्रम सिंह ने बताया कि टिहरी ज़िले के सुरकंडा मंदिर क्षेत्र में डॉपलर रडार लगाने का काम पूरा हो गया है।

प्रमुख बिंदु

- वर्तमान में रडार टेस्टिंग का काम चल रहा है, जिसके एक महीने के भीतर सुचारु तरीके से कार्य प्रारंभ करने की उम्मीद है।
- गौरतलब है कि जून 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद से सटीक मौसम पूर्वानुमान के लिये पर्वतीय क्षेत्र में रडार की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, लेकिन क्षेत्र में रडार स्थापित करने के लिये वर्षों से भूमि का चयन नहीं हो पाने के कारण रडार की स्थापना नहीं हो सकी थी।
- डॉपलर रडार से करीब दो घंटे पहले ही भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज़ हवाओं की संभावना की जानकारी मिल सकेगी।
- रडार 100 किलोमीटर के दायरे में मौसमी गतिविधियों पर डाटा रिकॉर्ड करने में सक्षम होगा।
- रडार से मौसम की सटीक जानकारी चारधाम सर्किट पर यात्रा करने वाले लोगों को भी दी जाएगी।

उत्तराखंड में आठ तल वाली गुफा की खोज

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तराखंड के गंगोलीहाट के गंगावली वंडर्स ग्रुप के सुरेंद्र सिंह बिष्ट, ऋषभ रावल, भूपेश पंत और पप्पू रावल ने एक आठ तल वाली गुफा की खोज की है।

प्रमुख बिंदु

- गुफा की चट्टानों पर शेषनाग सहित अन्य पौराणिक देवी-देवताओं का अंकन किया गया है।
- यह अब तक मिली गुफाओं में सबसे बड़ी गुफा है।
- गौरतलब है कि गंगावली क्षेत्र के शैल पर्वत शिखर पर मानस खंड में 21 गुफाओं का ज़िक्र है, जिनमें से 10 को खोजा जा चुका है।
- अब तक खोजी गई गुफाओं में पाताल भुवनेश्वर, कोटेश्वर, भोलेश्वर, महेश्वर, लाटेश्वर, मुक्तेश्वर, सप्तेश्वर, डाणेश्वर, भुगतुंग गुफा शामिल हैं।

उत्तराखंड के हर ज़िले में गठित होगी सड़क सुरक्षा समिति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तराखंड सड़क सुरक्षा के नोडल अधिकारी सुधांशु गर्ग ने बताया कि राज्य के प्रत्येक ज़िले में डीएम की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति गठित की जाएगी।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इन समितियों का गठन सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा।
- इसमें एसपी, सीएमओ, पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन, मंत्रालय के प्रतिनिधि, एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, निगम-पालिका के ईई एवं किसी सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि सदस्य, जबकि स्टेट हाईवेज के अधिकारी सदस्य सचिव होंगे।
- यह समिति हर ज़िले में सड़क सुरक्षा प्लान बनाएगी, जिसमें ज़िले में बड़े हादसे होने की स्थिति से निपटने के लिये इमरजेंसी मेडिकल प्लान भी शामिल होगा।
- महीने में कम-से-कम एक बार इस ज़िला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक होगी।
- गौरतलब है कि भारत ब्रासीलिया घोषणा का एक हस्ताक्षरकर्त्ता देश है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2020 तक सड़क दुर्घटनाओं और मृत्यु दर को 50 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य रखा गया था।

'1064 भ्रष्टाचार-रोधी मोबाइल ऐप'

चर्चा में क्यों ?

8 अप्रैल, 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित राज्य सचिवालय में '1064 भ्रष्टाचार-रोधी मोबाइल ऐप' का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इस ऐप को विजिलेंस विभाग द्वारा उत्तराखंड में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिये निर्मित किया गया है।
- यह ऐप हिन्दी एवं अंग्रेज़ी दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें कोई भी व्यक्ति 1064 नंबर पर ऐप के माध्यम से या फोन से शिकायत कर सकता है।
- यदि किसी शिकायतकर्त्ता की शिकायत विजिलेंस से संबंधित नहीं है, तो उसे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एवं संबंधित विभाग को भेजा जाएगा।
- ऐप के माध्यम से प्रत्येक शिकायत को रजिस्टर कर संबंधित डाटा की सुरक्षा के साथ शिकायतकर्त्ता की गोपनीयता का ध्यान रखा जाएगा।

नरेंद्र सिंह नेगी

चर्चा में क्यों ?

9 अप्रैल, 2022 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू द्वारा उत्तराखंड के नरेंद्र सिंह नेगी को लोक संगीत के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिये संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्रदान किया गया।

प्रमुख बिंदु

- नरेंद्र सिंह नेगी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से संबंधित हैं।
- इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 'गढ़वाली गीतमाला' से की थी तथा इनका पहला एल्बम 'बुराँश' था।
- इन्हें मोनाल पुरस्कार, गढ़कला शिरोमणि सम्मान आदि से सम्मानित किया जा चुका है।

प्लास्टिकमुक्त देहरादून अभियान

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में देहरादून के मेयर सुनील उनियाल ने बताया कि देहरादून नगर निगम के प्लास्टिकमुक्त देहरादून अभियान से 580 से भी अधिक विद्यार्थी वालंटियर जुड़ गए हैं।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस अभियान की शुरुआत 26 मार्च, 2022 को की गई थी।
- इसके अंतर्गत 30 अप्रैल तक शहर के 100 स्कूलों के 25,000 विद्यार्थियों एवं परिवारों तक पहुँचने का लक्ष्य रखा गया है।
- इसके तहत प्रत्येक भागीदार स्कूल में एक प्लास्टिक बैंक खोला गया है, जहाँ विद्यार्थी प्लास्टिक संग्रहण के बाद जमा कर देते हैं।
- गौरतलब है कि यह अभियान स्वच्छ सर्वेक्षण, 2022 के तहत लोगों की सहभागिता बढ़ाने तथा स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिये प्रारंभ किया गया है।

राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड-1 में उत्तराखंड

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड-1 से संबंधित रिपोर्ट में उत्तराखंड को फ्रंट रनर्स की श्रेणी में शामिल किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में उत्तराखंड की रैंक 5वीं, जबकि स्कोर 46.5 है।
- यह सूचकांक 2019-20 के आँकड़ों के आधार पर नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया है।
- गौरतलब है कि यह सूचकांक 6 मानकों- डिस्कॉम का प्रदर्शन, ऊर्जा दक्षता, पर्यावरणीय स्थिरता, स्वच्छ ऊर्जा पहल, नई पहल तथा पहुँच, वहनीयता एवं विश्वसनीयता के आधार पर जलवायु और ऊर्जा क्षेत्र में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा किये गए प्रयासों को ट्रैक करता है।
- विभिन्न मानकों के संदर्भ में उत्तराखंड का स्कोर निम्न प्रकार है-
- डिस्कॉम का प्रदर्शन- 61.9
- ऊर्जा दक्षता- 50.5
- पर्यावरणीय स्थिरता- 48.7
- नई पहल- 14.7
- स्वच्छ ऊर्जा पहल- 18.5
- पहुँच, वहनीयता एवं विश्वसनीयता- 55.3

हरिद्वार में गंगा घाटों पर प्लास्टिक वस्तुओं की बिक्री पर रोक

चर्चा में क्यों ?

12 अप्रैल, 2022 को हरिद्वार नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती की अध्यक्षता में निर्णय लिया गया कि 25 अप्रैल से हरिद्वार स्थित गंगा घाटों पर प्लास्टिक वस्तुओं की बिक्री नहीं की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- प्लास्टिक वस्तुओं पर रोक के पश्चात् घाटों पर हस्तनिर्मित कपड़े तथा जूट की चटाई के साथ प्लास्टिक कैन की जगह बाँस, तांबा व काँच की बोतल की बिक्री की जाएगी।
- यह बिक्री दीनदयाल अंत्योदय योजना तथा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत गठित महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से की जाएगी।
- गौरतलब है कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन वर्ष 2013 में आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा प्रारंभ किया गया था, जिसके अंतर्गत शहरी गरीबों को सशक्त आधारभूत स्तर की संस्थाओं में संगठित करने, कौशल विकास के लिये अवसर सृजित करने पर ज़ोर दिया जाता है।

नोट :

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की कवायद

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदेश में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिये गृह विभाग को नोडल विभाग के रूप में नामित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- इस निर्णय के पश्चात् गृह विभाग इसके लिये समिति गठित करने के साथ ही समान नागरिक संहिता का ड्रॉफ्ट तैयार करेगा।
- गौरतलब है कि सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में ही इसके लिये समिति बनाने का निर्णय लेते हुए कहा था कि समिति में विधि एवं कानून के साथ ही अन्य क्षेत्रों से संबंधित विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा।
- इसके लिये न्याय विभाग को नोडल विभाग बनाते हुए इसका ड्रॉफ्ट तैयार करने की ज़िम्मेदारी सौपी गई थी, जिसमें अब परिवर्तन करते हुए यह ज़िम्मा गृह विभाग को सौंपा गया है।
- उल्लेखनीय है कि समान नागरिक संहिता संबंधी प्रावधान संविधान के भाग-4 के अंतर्गत अनुच्छेद-44 में दिया गया है।
- वर्तमान में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है, जहाँ समान नागरिक संहिता लागू है।

बद्रीनाथ मास्टर प्लान

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय में उप-सचिव मंगेश घिल्डियाल ने बद्रीनाथ का दौरा कर बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत किये जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया।

प्रमुख बिंदु

- घिल्डियाल ने बद्रीनाथ मंदिर परिसर, माना बाइपास, बद्रीश और शेषनाग झील, अलकनंदा नदी तट, साकेत चौराहा, अस्पताल, बस स्टेशन और आसपास के अन्य स्थलों सहित विभिन्न स्थानों का निरीक्षण कर प्लान में निर्धारित सभी परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने का निर्देश दिया।
- गौरतलब है कि मास्टर प्लान प्रोजेक्ट के सभी कार्यों को तीन चरणों में पूरा किया जाना है-
- पहले चरण में लेक फ्रंट डेवलपमेंट, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, अराइवल प्लाजा, सिविक एमेनिटी सेंटर, लूप रोड, अस्पताल का विस्तार और बीआरओ रोड जैसे कार्यों का निष्पादन शामिल होगा।
- दूसरे चरण में बद्रीनाथ मंदिर के आस-पास स्थित स्थलों का विकास होगा।
- तीसरे चरण में सरोवर से लेकर मंदिर तक आस्था पथ निर्माण व अन्य कार्य शामिल होंगे।

पंतनगर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा बनाने की पैरवी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने ऊधमसिंह नगर ज़िले के पंतनगर एयरपोर्ट का विस्तारीकरण कर नया ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा बनाने के साथ एयरपोर्ट को आईएफआर (इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स) के तहत आधुनिक उपकरण लगाने के संबंध में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखा है।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि सरकार द्वारा ऊधमसिंह नगर के पंतनगर में नया ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा विकसित करने के लिये सारी औपचारिकताएँ पूरी करने के साथ ही नियमानुसार भूमि का हस्तांतरण भी किया जा चुका है।

नोट :

- गौरतलब है कि पंतनगर के पास सिडकुल क्षेत्र में Integrated Industrial Estate के साथ-साथ कई बड़े उद्योग स्थापित हैं।
- इसके अतिरिक्त यहाँ नानक सागर डैम, कौसानी, माँ पूर्णागिरि सिद्धपीठ, चितई गोलू देवता मंदिर, पानडूखोली, महावतार बाबा की गुफा, मुनस्यारी, चौकड़ी, द्वाराहाट, दूनागिरी का सिद्धपीठ सहित कई धार्मिक व पर्यटन स्थल भी मौजूद हैं।

व्यासी जल-विद्युत परियोजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तराखंड जल-विद्युत निगम लिमिटेड के एम.डी. संदीप सिंघल ने बताया कि व्यासी जल-विद्युत परियोजना के सभी ट्रायल पूरे हो चुके हैं तथा इससे 19 अप्रैल से उत्तराखंड को बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- व्यासी जल-विद्युत परियोजना विकास नगर के निकट लोहारी में यमुना नदी पर स्थापित की गई है।
- 120 मेगावाट की इस परियोजना से उत्तराखंड को 353 मिलियन यूनिट बिजली वार्षिक मिलेगी, जबकि 0.72 मिलियन यूनिट दैनिक बिजली रूटीन समय में और 60 मेगावाट बिजली सुबह-शाम पीक ऑवर्स में मिलेगी।
- गौरतलब है कि वर्तमान में यूपीसीएल को लगभग 31 मिलियन यूनिट बिजली उपलब्ध हो रही है, जबकि डिमांड 44 मिलियन यूनिट तक पहुँच रही है। ऐसे में इस परियोजना से मिलने वाली बिजली से यूपीसीएल को कुछ राहत मिलेगी।

चंद्रभागा नदी

चर्चा में क्यों ?

19 अप्रैल, 2022 को कूड़ा डंपिंग ज़ोन बनती जा रही चंद्रभागा नदी को साफ करने के लिये मुनि की रेती नगर पालिका प्रशासन ने विशेष स्वच्छता अभियान चलाकर कूड़ा-कचरा एकत्रित कर उसका निस्तारण किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अभियान के तहत नगर पालिका अध्यक्ष रोशन रतूड़ी और अधिशासी अधिकारी तनवीर मारवाह के नेतृत्व में सफाईकर्मियों ने ढालवाला क्षेत्र के समीप चंद्रभागा नदी में जहाँ-तहाँ बिखरे कूड़े-कचरे को एकत्रित कर निस्तारण के लिये ट्रंचिंग ग्राउंड भेजा गया।
- साथ ही पालिकाकर्मियों ने चंद्रभागा नदी के अस्तित्व को बचाने के लिये लोगों से उसे स्वच्छ रखने की अपील करने के साथ ही आस-पास के लोगों को हिदायत दी गई कि नदी में गंदगी फेंकने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
- गौरतलब है कि चंद्रभागा गंगा की सहायक नदी है, जो टिहरी ज़िले के बनाली-कश्मालीधर से निकलने के बाद ऋषिकेश के मायाकुंड में गंगा नदी से मिल जाती है।

एचसी सेमवाल बने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान समिति के अध्यक्ष

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत सरकार ने उत्तराखंड के महिला और बाल विकास सचिव, एच.सी. सेमवाल को संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के कार्यान्वयन ढाँचे पर पुनर्विचार हेतु गठित समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है।

प्रमुख बिंदु

- यह समिति 2018-19 से 2021-22 तक लागू आरजीएसए के अनुभवों और संशोधित आरजीएसए के अनुरूप परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए संशोधित आरजीएसए के कार्यान्वयन ढाँचे को तैयार कर 15 दिनों के भीतर संशोधित रूपरेखा प्रस्तुत करेगी।

नोट :

- उल्लेखनीय है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2026 की अवधि के दौरान कार्यान्वयन हेतु 'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान' (RGSA) की संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना को जारी रखने की मंज़ूरी दी है। यह योजना अब 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट की अवधि के साथ समाप्त होगी।
- RGSA को पहली बार वर्ष 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 तक की अवधि के लिये मंज़ूरी दी गई थी। इस योजना का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं (PRI) की शासन क्षमताओं को विकसित करना है।
- इसका कार्यान्वयन पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।

चंपावत में बनेगा हाई-टेक मधुमक्खीपालन प्रशिक्षण केंद्र

चर्चा में क्यों ?

21 अप्रैल, 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित शहद निष्कर्षण कार्यक्रम के दौरान चंपावत में प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के संबंध में बागवानी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री धामी ने हाल ही में मुख्यमंत्री आवास के परिसर को बागवानी गतिविधियों के मॉडल के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया था, ताकि मुख्यमंत्री आवास पर आने वाले लोगों को बागवानी में आधुनिक तकनीकों के बारे में प्रत्यक्ष अनुभव और जानकारी मिल सके।
- इस अवसर पर बागवानी निदेशक हरमिंदर सिंह बावेजा ने बताया कि मधुमक्खियाँ शहद उत्पादन के अलावा परागण को बढ़ाकर कृषि उत्पादन में वृद्धि करती हैं।
- इसी तरह रॉयल जेली, प्रोपोलिस, मधुमक्खी मोम, पराग, कोंब हनी और बी वेनम जैसे उत्पाद भी मधुमक्खीपालकों द्वारा तैयार किये जाते हैं।
- गौरतलब है कि मीठी क्रांति मधुमक्खीपालन को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार की एक महत्त्वाकांक्षी पहल है, जिसे 'मधुमक्खीपालन' (Beekeeping) के नाम से जाना जाता है। मीठी क्रांति को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा वर्ष 2020 में (कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत) राष्ट्रीय मधुमक्खीपालन और शहद मिशन शुरू किया गया।

'प्रवेश उत्सव'

चर्चा में क्यों ?

20 अप्रैल, 2022 को उत्तराखंड के शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने राजकीय इंटर कॉलेज श्रीनगर से एक व्यापक नामांकन अभियान 'प्रवेश उत्सव' की शुरुआत की।

प्रमुख बिंदु

- यह व्यापक नामांकन अभियान राज्य के सरकारी स्कूलों में छात्र नामांकन बढ़ाने के लिये उत्तराखंड के शिक्षा विभाग द्वारा चलाया जा रहा है।
- 10 दिवसीय 'प्रवेश उत्सव' अभियान का संचालन 30 अप्रैल तक किया जाएगा।
- शिक्षा विभाग अपने ज़िले में अभियान में उच्चतम नामांकन प्राप्त करने वाले शीर्ष दस स्कूलों को एक कंप्यूटर प्रणाली प्रदान करेगा।
- उत्तराखंड में विद्यार्थी नामांकन अनुपात निम्न प्रकार है-

उत्तराखंड	प्राथमिक (1 से 5)			उच्च प्राथमिक (6 से 8)			एलीमेंट्री (1 से 8)		
	लड़के	लड़कियाँ	कुल	लड़के	लड़कियाँ	कुल	लड़के	लड़कियाँ	कुल
	113.7	116.7	115.2	97.3	99.2	98.2	107.3	109.7	108.5

(स्रोत: भारतीय राज्यों पर सांख्यिकी की हैंडबुक, आरबीआई)

नोट :

वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून में मनाया गया पृथ्वी दिवस

चर्चा में क्यों ?

22 अप्रैल, 2022 को वन अनुसंधान संस्थान (FRI), देहरादून में पृथ्वी दिवस मनाया गया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर एफआरआई निदेशक रेणु सिंह ने कहा कि पृथ्वी दिवस हमें अपने ग्रह को बचाने की दिशा में काम करने की हमारी ज़िम्मेदारियों की याद दिलाता है, क्योंकि यह पारिस्थितिक मुद्दों की ओर एक संकेतक के रूप में कार्य करता है।
- 2022 के लिये पृथ्वी दिवस की आधिकारिक थीम 'इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट' (Invest in Our Planet) है।
- इसमें पाँच प्राथमिक कार्यक्रम शामिल हैं- ग्रेट ग्लोबल क्लीनअप, सस्टेनेबल फैशन, क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंटल लिटरेसी, कैनोपी प्रोजेक्ट, फूड एंड एनवायरनमेंट और ग्लोबल अर्थ चैलेंज।

क्रांति दिवस मेला

चर्चा में क्यों ?

23 अप्रैल, 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी ज़िले के पीठसैंण क्षेत्र के मासौ चोपड़ाकोट में क्रांति दिवस मेले में शिरकत की।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने पेशावर कांड के महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की स्मृति में मनाए जाने वाले क्रांति दिवस मेले को प्रतिवर्ष राजकीय मेले के रूप में मनाए जाने की घोषणा की।
- गौरतलब है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 23 अप्रैल, 1930 को ब्रिटिश रॉयल गढ़वाल राइफल के हवलदार मेजर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने ब्रिटिश हुकूमत के निहत्थे पठानों पर गोली चलाने के निर्देशों को मानने से इनकार कर दिया था।
- आज्ञा न मानने के कारण इन गढ़वाली सैनिकों पर मुकदमा चलाया गया, जिसकी पैरवी मुकुंदी लाल द्वारा चलाई गई थी।
- मुकदमे के पश्चात् 1930 में चंद्र सिंह गढ़वाली को 14 साल के कारावास के लिये ऐबटाबाद की जेल में भेज दिया गया, किंतु बाद में इनकी सज़ा कम कर 11 वर्ष के कारावास के बाद इन्हें 26 सितंबर, 1941 को रिहा कर दिया गया।

उत्तराखंड के लिये 13,707 करोड़ रुपए की मेगा निर्माण परियोजना का प्रस्ताव

चर्चा में क्यों ?

26 अप्रैल, 2022 को सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के अधिकारियों ने उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाकों के लिये 13,707 करोड़ रुपए के मेगा निर्माण पैकेज के तहत प्रस्तावित परियोजनाओं का उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह को प्रेजेंटेशन दिया।

प्रमुख बिंदु

- प्रेजेंटेशन में बताया गया कि बीआरओ द्वारा उत्तराखंड में 9,250 करोड़ रुपए की लागत से 14 नई सड़कों एवं 77.50 करोड़ रुपए की लागत से पाँच हेलीपोर्ट का निर्माण, 12 करोड़ रुपए के बजट से गौचर और नैनी सैनी हवाई पट्टी का विस्तार तथा 4,260 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से दो सुरंगों का निर्माण किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने 26 अप्रैल को ही राजभवन में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के 'बहुआयामी अभियान' को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
- बीआरओ ने इस अभियान का शुभारंभ अपने 63वें स्थापना दिवस और देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में किया है। इस अभियान का विषय 'राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र निर्माण' है।

नोट :

उत्तराखंड में बढ़ता वनाग्नि का प्रकोप

चर्चा में क्यों ?

27 अप्रैल, 2022 को उत्तराखंड के मुख्य वन संरक्षक, वनाग्नि एवं आपदा प्रबंधन कार्यालय की ओर से जारी आँकड़ों के अनुसार प्रदेश के गढ़वाल और कुमाऊँ, दोनों मंडलों में वनाग्नि की सबसे अधिक घटनाएँ सामने आई हैं।

प्रमुख बिंदु

- प्रदेश में कुल 227 स्थानों पर जंगलों में आग लगी, जिसमें कुल 561 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है तथा इससे 11 लाख रुपए से अधिक की आर्थिक क्षति का आकलन किया गया है।
- 15 फरवरी से शुरू हुए फायर सीजन में इस वर्ष अब तक वनाग्नि की कुल 1443 घटनाएँ सामने आ चुकी हैं, जिनमें गढ़वाल में 642, कुमाऊँ में 724 और संरक्षित वन्य जीव क्षेत्र की 77 घटनाएँ शामिल हैं। इनसे 2432.62 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित होने के साथ ही 60 लाख रुपए से अधिक की आर्थिक क्षति का आकलन किया गया है।
- वनाग्नि ने उत्तराखंड में वायु को प्रदूषित कर दिया है। वनाग्नि की घटनाओं के कारण यहाँ ब्लैक कार्बन की मात्रा में 12 से 13 गुना वृद्धि हुई है। वायुमंडल में इस ब्लैक कार्बन की गणना के लिये केंद्रीय गढ़वाल विश्व विद्यालय के भौतिकी विभाग में भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) के सहयोग से एथेलोमीटर स्थापित किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि वन सीमांत समुदायों को सूचित, सक्षम और सशक्त बनाने तथा उन्हें राज्य वन विभागों के साथ काम करने के लिये प्रोत्साहित करके जंगल की आग को कम करने हेतु 2018 में जंगल की आग पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPFF) शुरू की गई थी।

सूर्यधार झील

चर्चा में क्यों ?

29 अप्रैल, 2022 को उत्तराखंड के सिंचाई एवं लघु सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने विभागीय समीक्षा बैठक में कहा कि सूर्यधार झील की गहराई को बिना अनुमति के 7 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर कर दिया जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

प्रमुख बिंदु

- सूर्यधार झील परियोजना के निर्माण की घोषणा 29 जून, 2017 को तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की थी।
- सूर्यधार झील उत्तराखंड में स्थित है। डोईवाला के भोगपुर में जाखम नदी पर बनाई गई सूर्यधार झील का उद्घाटन उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 29 नवंबर, 2020 को किया था।
- यह एक बहु-उद्देशीय झील है, जिसकी धारण क्षमता 77 हज़ार घन मीटर है। यह झील 550 मीटर लंबी, 28 मीटर चौड़ी एवं 10 मीटर गहरी है। इस झील से लगभग 18 गाँवों को सिंचाई और 19 गाँवों को पेयजल मिलेगा।
- इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ क्षेत्र का विकास भी होगा।

उत्तराखंड में मुख्यमंत्री से की गई शिकायतों का होगा त्वरित निपटान

चर्चा में क्यों ?

29 अप्रैल, 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में मुख्यमंत्री संदर्भों और पत्रों के ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की।

प्रमुख बिंदु

- इस पोर्टल के माध्यम से शिकायतें संबंधित विभागों तक एक क्लिक से ही पहुँच जाएंगी, जिससे इन शिकायतों का तीव्र निपटारा किया जा सकेगा।
- गौरतलब है कि अब तक मुख्यमंत्री कार्यालय को संबोधित पत्रों को मुख्यमंत्री लेटर मॉनिटरिंग पैकेज के माध्यम से पंजीकृत कर भौतिक रूप से संबंधित विभागों को भेजा जाता रहा है।
- इसके अलावा अब मुख्यमंत्री को भेजी जाने वाली शिकायतों और पत्रों को सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 के साथ एकीकृत किया गया है।

नोट :